

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 5/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जय्य :- श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री दीपचन्द पुत्र श्री धूली लाल उम्र-27 निवासी जैन मन्दिर के पास श्री जी चौक वार्ड नं0 32 बारां(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स दीपचन्द मनीष कुमार, हॉस्पिटल रोड बारां।
2. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री नन्द किशोर, मैसर्स नरेश कुमार सुरेश कुमार, शिवाजी कॉलोनी चौराहा मेन शाहबाद रोड बारां।
3. श्री गिरिशा नेमा पुत्र श्री लल्लू राम नेमा,(नोमिनि) निवासी 1701 टावर-11, दक्षिण के पास सेक्टर 50, गुडगॉव, नई दिल्ली ITC LIMITED, D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Privthviraj Road C-scheme, Jaipur-302001, Jaipur(Raj.)
4. ITC LIMITED, D-24, Office No.201, Durlabh Chambers, Privthviraj Road C-scheme, Jaipur-302001,)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वयं)

2- श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण क. सं. 1व 2)

3- श्री मनीष प्रियदर्शी अभिभाषक (अप्रार्थीगण क. सं. 3व 4)

निर्णय दिनांक 14.10.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.06.2015 को मैसर्स दीपचन्द मनीष कुमार, हॉस्पिटल रोड बारां पर पहुंचा। वहाँ पर श्री दीपचन्द पुत्र श्री धूली लाल की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 09.06.2015 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/ एच/ पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारां के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ नुडल्स(प्रोपराइटी फूड)(यप्पी) 70ग्रा. के 50 पैकेट विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ नुडल्स(प्रोपराइटी फूड)(यप्पी) मे

मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **नुडल्स(प्रोपराइटरी फूड)(यप्पी)** 70ग्रा. के 32 पैकेट को वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री दीपचन्द पुत्र श्री धूली लाल को 300/-रु. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहन श्री राकेश गैरा जैन व श्री सोनु मालव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **नुडल्स(प्रोपराइटरी फूड)(यप्पी)** 70ग्रा. के 32 पैकेट मूल को चार भागों में विभाजित कर खाली साफ एवं सूखे डिब्बों में भरा गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच-480 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-2 कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बरों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच-480 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूने पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दीपचन्द पुत्र श्री धूली लाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सीलड लिफाफे में श्री मुरलीधर सुमन च.श्रै. कर्मचारी कार्यालय बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/292 दिनांक 10.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./ 1694 / Act / 2015 / 849 दिनांक 07.09.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **नुडल्स (प्रोपराइटरी फूड) (यप्पी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिथ्याछाप(Misbranded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स दीपचन्द मनीष कुमार, हॉस्पिटल रोड बारां से पत्रांक 293 दिनांक 10.09.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल प्रति चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र एवं क्रय बिल की छाया प्रति पेश की गई। मैसर्स नरेश कुमार सुरेश कुमार, शिवाजी कॉलोनी चौराहा मेन शाहबाद रोड बारां (डिलर) को लिखे गये पत्र 308 दिनांक 21.

09.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, फर्म मालिक, पार्टनर व वाणिज्य कर रजि० की प्रति चाही गई जिसके प्रतिउत्तर में फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल संलग्न कर पेश किया गया। ITC LIMITED, C/o Bikaner golden Transport Corp. Near Sun city, Village Bad Pipli, NH-11, Sikar Highway, Jaipur से पत्रांक 327 दिनांक 06.10.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, नोमिनी आई.डी. पार्टनर व वाणिज्य कर रजि. की प्रति चाही गई, उन्होने जिसके प्रतिउत्तर में नोमिनि फॉर्म नं०-9, वेट-03 फॉर्म, एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति भिजवाई गई जिसमें श्री गिरिशा नेमा पुत्र श्री लल्लू राम नेमा (नोमिनि) ITC LIMITED, C/o Bikaner golden Transport Corp. Near Sun city, Village Bad Pipli, NH-11, Sikar Highway, Jaipur का होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 01.04.2016 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर अंतिम सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नुडल्स(प्रोपराइटी फूड)(यप्पी)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच में **मिथ्याछाप(Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संग्रहण के समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की आज्ञापक धारा-47(1) का अनुपालन नहीं किया व नमूना कार्यवाही के प्रारूप 5(क) की सूचना विपक्षी कम्पनी पर तामील नहीं की, जिसके कारण विपक्षी विनिर्माता कम्पनी संग्रहित नमूने के दूसरे भाग की जॉच प्रत्यायित प्रयोगशाला से कराने के अपने महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो गयी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2015(1) F.A.C.56 **मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि०** बनाम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में अपने निर्णय में धारा-47(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को आज्ञापक घोषित किया है।

यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-46(4) के अनुसार विपक्षी खाद्य विश्लेषक की आख्या के विरुद्ध अपील अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है व यदि अभिहित अधिकारी उचित समझता है, तो मामले को रैफरल प्रयोगशाला को भेजेगा। उक्त मामले में खाद्य विश्लेषक की आख्या प्राप्त होने के पश्चात धारा-46(4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि० 2006 का नोटिस अभिहित अधिकारी बारां द्वारा विपक्षी विनिर्माता कम्पनी को दिया ही नहीं गया। उपरोक्त कारण से विपक्षी विनिर्माता कम्पनी एक बार पुनः नमूने के दूसरे भाग की रैफरल लैब से कराने के अपने अधिकार से वंचित हो गयी। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 2015(2) F.A.C. 340 **मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि०** बनाम राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा-46(4) के अन्तर्गत खाद्य व्यापारकर्ता को दिये गये अधिकार को उसका कानूनी अधिकार घोषित किया है। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा रिट पिटीशन सं० 19499/2014 में दिनांक 22-07-2016 को निर्णय पारित कर यह अवधारित किया है कि यदि विपक्षी कम्पनी पर प्रारूप-5क तामील नहीं किया गया है और ना ही खाद्य विश्लेषक की आख्या धारा-46(4) के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है तो इसका अभिप्राय है कि विपक्षी को उसके मूल्यवान कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उससे बचाव का अवसर छीन लिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरुद्ध प्रारम्भ की गयी कानूनी प्रक्रिया शून्य होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-46(4) के समान ही खाद्य विश्लेषक की आख्या के विरुद्ध नमूने के दूसरे भाग की जॉच कराने का अधिकार पूर्व प्रचलित अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम-1954 की धारा-13(2) में विपक्षी को

प्राप्त था, जिसके बारे में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2018 (1) F.A.C. 355 राज्य बनाम् इस्माइल अयूब साहेब नादेफ में अपने निर्णय में अवधारित किया गया है कि उक्त धारा का अनुपालन मात्र औपचारिकता नहीं है यह विपक्षी का नमूने की जाँच केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराने का मूल्यवान अधिकार है। इस मामले में विपक्षी के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विपक्षी को नमूने के दूसरे भाग की जाँच कराने का अवसर नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2018 (1) F.A.C. 388 महेश यादव एवं अन्य बनाम् राजस्थान राज्य एवं अन्य में अवधारित किया है कि नमूने के दूसरे भाग की जाँच उच्च प्रयोगशाला से कराने के कानूनी अधिकार का हनन होने पर कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ही 2017(2) F.A.C.390 बापूलाल यादव बनाम् राजस्थान राज्य में अवधारित किया है कि खाद्य विश्लेषक की जाँच आख्या के विरुद्ध नमूने की जाँच केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराने का विपक्षी का अधिकार कानूनी व मूल्यवान है। इस हेतु आज्ञापक रूप से नोटिस दिया जाना व यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि नोटिस दिया गया है, साथ ही दिया गया है, से अभिप्राय विपक्षी पर तामील से है।

यह कि उक्त वाद में नमूना संख्या-एएच-480 की जाँच मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर के द्वारा की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-3(पी) एवं धारा-43 के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत धारा-47 के अनुसार लिये गये नमूने की जाँच उस खाद्य प्रयोगशाला द्वारा की जायेगी जो एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्कीडेटेड हो साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (F.S.S.A.I.) द्वारा अधिसूचित हो। उक्त जाँच मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर न तो एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्कीडेटेड है और ना ही F.S.S.A.I द्वारा अधिसूचित। माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा 2015 (1) F.A.C. 56 मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि० बनाम् भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं अन्य में निर्णय पारित करते समय उक्त बिन्दू की विस्तृत विवेचना की है व निर्णय के पैरा 93 में विस्तार से वर्णन करते हुए अवधारित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत संग्रहीत नमूने की जाँच करने वाली खाद्य प्रयोगशाला को दो शर्तों का पालन करना अनिवार्य है प्रथम व एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्कीडेटेड हो व द्वितीय F.S.S.A.I. द्वारा अधिसूचित हो एवं उक्त दोनों ही शर्तों का पूरा किया जाना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में ऐसी प्रयोगशाला की आख्या पर विधिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। नमूने के विश्लेषण के समय राजस्थान राज्य हेतु एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्कीडेटेड उन खाद्य प्रयोगशाला की सूची जो F.S.S.A.I. द्वारा अधिसूचित है लिखित बहस के साथ संलग्न की जा रही है।

यह कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक- L.S./1694/Act/2015/849 दिनांक 07.09.2015 द्वारा नमूना संख्या-एएच-480 को **मिथ्याछाप(Misbranded)** घोषित किया गया है। नमूना संख्या एएच-480 **नुडल्स(प्रोपराइटरी फूड)(यप्पी)** का था, जिसके मूल पैक में दो खाद्य पदार्थ मौजूद थे, एक नूडल्स व द्वितीय टेस्ट मेकर अर्थात् सीजनिंग जो कि प्रोपराइटरी फूड है। एफएसएसएआई द्वारा प्रार्थी/विनिर्माता कम्पनी के उक्त उत्पाद को प्रोडक्ट एप्रूबल दिया गया है।

यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम-3.1.2 के अनुसार अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए कारमल रंग किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 की (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम-2011 की सारिणी-10 के अनुसार टेस्ट मेकर (सीजनिंग) में जीएमपी (गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस) के आधार पर कारमल रंग मिलाया जा सकता है। यह कि एफएसएसएआई की एडवाइजरी दिनांक 08-06-2015 एवं वर्ष-2016 में जारी सातवें संशोधन के अन्तर्गत सीजनिंग में कारमल रंग की उपस्थिति अनुज्ञप्त नहीं थी। किन्तु पुनः 28-12-2017 को एफएसएसएआई के निर्देशन एवं दिनांक 12-11-2018 को जारी

शासकीय गजट के अनुसार टेस्टमेकर (सीजनिंग) में कारमल रंग 10 हजार मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिलाया जा सकता है।

यह कि खाद्य विश्लेषक ने टेस्ट मेकर के पाउच पर आवश्यक जानकारियां अंकित न होने के कारण नमूना को **मिथ्याछाप(Misbranded)** घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण है व अधिनियम की मंशा के विपरीत है। क्योंकि उक्त टेस्ट मेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है जिससे ग्राहक को उक्त खाद्य के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ग्राहक खाद्य के क्रय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचना के आधार पर ही खाद्य क्रय करता है। साथ ही पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक रूप से बिक्री हेतु नहीं है और साथ ही उस पर सूचनायें अंकित करने में मुद्रण स्याही खाद्य (नूडल्स) के सीधे सम्पर्क में आ जायेगी, जिससे खाद्य के असुरक्षित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में यह उद्घोषणा की है कि खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम-2011 के विनियम 2.2 के अनुसार प्रत्येक पूर्व पैक खाद्य पर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक जानकारियां अंकित होंगी। साथ ही विनियम 1.2.8 के अनुसार पूर्व पैक खाद्य से अभिप्राय खाद्य जो किसी भी प्रकार के पैकेज में इस प्रकार रखा गया है कि उसके तत्व को पैकेज को बिना क्षतिग्रस्त किये बदला न जा सके और जो ग्राहक को बिक्री हेतु तैयार है। विपक्षी कम्पनी का बाह्य पैक पूर्व पैक खाद्य की श्रेणी में आता है व उस पर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक समस्त जानकारियाँ अंकित की गयी हैं।

यह कि प्रार्थी/विपक्षी विनिर्माता कम्पनी का उत्पाद विनिर्मित है अतः एफएसएसएआई की एडवायजरी दिनांक 08-06-2015 उक्त उत्पाद पर लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि इस प्रकार एडवायजरी अपने जारी होने के दिनांक से भी पूर्व समय से प्रभावी हो जायेगी। अर्थात् उसका भूतलक्षी प्रभाव होगा। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

यह कि एफएसएसएआई की एडवायजरी दिनांक 08-06-2015 भी विधिक दृष्टि से शून्य है व विधिक उपबन्धों के विपरीत है। एफएसएसएआई द्वारा उक्त एडवायजरी में नूडल्स व टेस्टमेकर के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि02006 की धारा-16 (2) का विषय है जिसको प्रभाव में लाने के लिए धारा-92 एवं 93 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है जिसका अनुपालन उक्त एडवायजरी के मामले में नहीं किया गया है। यह कि पूर्व में भी ऐसी एडवायजरी एफएसएसएआई द्वारा जारी की गयी थी, जिसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं02746/ 2013 व्हाइटल न्यूट्रासिटीकल प्रा0लि0 अन्य बनाम् भारत संघ में निर्णय दिनांक 01-08-2014 द्वारा यह कहकर शून्य कर दिया गया कि एफएसएसएआई द्वारा धारा-16 (2) के विषय पर जारी एडवायजरी कानून का प्रभाव नहीं रखती, यदि वह धारा-92 व 93 के अनुपालन में संसद के दोनों सदनों के समक्ष न रखी गयी हो। यह कि एफएसएसएआई द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत स्पेशल रिट पिटीशन (सिविल) 23772-74/2014 भी उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी व बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश पुष्ट कर दिया गया।

यह कि विपक्षी विनिर्माता कम्पनी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी उल्लंघन/अपराध नहीं किया है व उक्त न्याय निर्णायक कार्यवाही न्यायहित में रद्द किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि धारा 47(1) एवं धारा 46(4) की पालना में अप्रार्थी क्रम 1 को मुख्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1694/Act/2015/849 दिनांक 07.09.2015 के बाद खाद्य पदार्थ **नूडल्स(प्रोपराइटरी फूड)(यप्पी)** की

पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ने पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कि निर्माता कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु उनके द्वारा पुनः जांच नहीं करवायी गई है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण में प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1694/Act/2015/849 दिनांक 07.09.2015 व दोनों पक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों की गहनता से मनन एवं विश्लेषण किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैंगी नूडल्स की निर्मात्री कम्पनी नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक है और सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल केशमेमों द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मैंगी नूडल्स की जांच एफएसएसएआई की एडवाइजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर जांच की गई, जिस एडवाइजरी में दिये गये स्टेण्डर्ड के तहत कलर नहीं होना चाहिए, किन्तु मूल पैकेट के अन्दर रख कर मसाला पाउच पर किसी प्रकार की लैबलिंग सूचना नहीं पाये जाने पर **मिथ्याछाप (Mis Branded)** घोषित किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया कि एडवाइजरी नमूना लेने की दिनांक के पश्चात जारी की गई है एवं कम्पनी द्वारा अन्दर रखे मसाला पैकेट पाउच की पूर्ण जानकारी बाहरी कवर पर पूर्णतः से एकट अनुसार अंकित की गई है एवं बताया गया की नमूना लेने की दिनांक तक प्रोपराइटीरी फूड मैंगी नूडल्स के मानक तय नहीं होने से कम्पनी द्वारा नियमों की पालना कराया जाना सम्भव नहीं था। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा खाद्य पदार्थ मैंगी नूडल्स की पूर्ण जांच एडवाइजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर जांच किये जाने से रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है तथा प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां
(राज.)

